



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रतिपक्षर से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Handwritten signature and stamp.

सं. 2] नई दिल्ली, रविवार, जनवरी 1, 1995/पौष 11, 1916
No. 2] NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 1, 1995/PAUSA 11, 1916

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिमूचना
नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1995
सं. 1/95—सीमा शुल्क

मा. का. नि. 2(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (7) और धारा 9ग की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, और सीमा शुल्क टैरिफ (बाउन्डीशन वस्तु की पहचान, उस पर शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1985 को उन नानों के सिवाय अधिकांत करने हुए, जिन्हें ऐसे अतिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा शुल्क टैरिफ (सहायिकी वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) अभिप्रेत है;

(ख) “घरेलू उद्योग” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) वैसे ही वस्तुओं के समस्त घरेलू उत्पादक; या घरेलू उत्पादक, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन, उक्त वस्तु के कुछ घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात तब के सिवाय बनता है जब ऐसे उत्पादक अभिकथित साहायिकी/वस्तु के लिए निर्यातकर्ताओं या आयातकर्ताओं के नातीदार हैं या वह स्वयं उसके आयातकर्ता हैं। ऐसी दशा में, ऐसे उत्पादकों को घरेलू उपयोग का भाग नहीं समझा जाएगा और “घरेलू उद्योग” पद शेष उत्पादकों के बारे में होगा।

परन्तु इन नियमों के नियम 13 के उपनियम (3) में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, प्रश्नगत वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग में दो या अधिक प्रतियोगी बाजार समाविष्ट समझे जाएंगे और ऐसे प्रत्येक बाजार के भीतर उत्पादकों को अलग उद्योग समझा जाएगा, यदि—

(i) ऐसे बाजार के भीतर उत्पादक प्रश्नगत वस्तु का अपने सभी या लगभग सभी उत्पादन का उस बाजार में विपणन करने है ; और

(ii) बाजार मांग की, राज्यक्षेत्र में अन्यत्र अवस्थित उक्त वस्तु के उत्पादकों द्वारा पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नहीं की जाती है ;

(ग) “हितवद् पक्षकार” के अन्तर्गत निम्नलिखित है—

(i) किसी ऐसी वस्तु का, जो माहायिकी दिष्ट जाने के लिए अन्वेषण के अधीन है, कोई निर्यातकर्ता या विदेशी उत्पादक या आयातकर्ता या किसी व्यापार या कारवार संगम जिसके बहुसंख्यक सदस्य ऐसी वस्तु के उत्पादक, निर्यातकर्ता या आयातकर्ता हैं ;

(ii) भारत में वैसी ही वस्तु का कोई उत्पादक या कोई व्यापार और कारवार संगम जिसके बहुसंख्यक सदस्य वैसी ही वस्तु का भारत में उत्पादन करने हैं ;

(घ) “अन्तिम शृङ्खला” से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित प्रतिशुल्क अभिप्रेत है ;

(ङ) “विनिर्दिष्ट देश” से ऐसा देश या राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और उसके अन्तर्गत वह देश या राज्यक्षेत्र है जिसके साथ भारत सरकार का सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्रीय व्यवहार प्रदान करने के लिए करार किया है ।

(च) उन सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में उनके हैं ।

3. अभिहित प्राधिकारी की नियुक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पक्ति के नीचे कान हो या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे वह सरकार ठीक समझे, इन नियमों के प्रयोजन के लिए अभिहित प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार अभिहित प्राधिकारी को ऐसे अन्य व्यक्तियों की सेवाएं और ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है जो वह ठीक समझे ।

4. अभिहित प्राधिकारी के कर्तव्य—अभिहित प्राधिकारी को इन नियमों के अनुसार निम्नलिखित कर्तव्य होंगे—

(क) किसी वस्तु के आयात के संबंध में किसी महायिकी की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव के बारे में अन्वेषण करना ;

(ख) ऐसी वस्तु की पहचान करना, जो प्रतिशुल्क की दायी है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित के बारे में अपना अन्तिम या अन्यथा निष्कर्ष प्रस्तुत करना—

(i) अन्वेषणाधीन वस्तु के संबंध में महायिकी की प्रकृति और रकम ; और

(ii) विनिर्दिष्ट देश से ऐसी वस्तु के आयात के परिणामस्वरूप भारत में स्थापित किसी उद्योग को क्षति या क्षति की आशंका या भारत में किसी उद्योग के स्थापन में नातिक्रम गतिरोध ।

(घ) प्रतिशुल्क की ऐसी रकम जो यदि उद्घृष्ट की जाएगी तो घरेलू उद्योग को क्षति वृद्ध करने के लिए पर्याप्त होगी और ऐसे शुल्क के प्रारंभ की तारीख की सिफारिश करना ; और

(ङ) प्रतिशुल्क के जारी रखने की आवश्यकता का पुनर्विचार करना ।

5. उद्भव के देश के बारे में विनिश्चय—ऐसे मामलों में जहां वस्तुओं का उद्भव के देश में सीधे आयात नहीं किया जाता है किन्तु किसी मध्यवर्ती देश में आयात किया जाता है, इन नियमों के उपबंध पूर्ण रूप से लागू होंगे और ऐसा कोई संभववहार इन नियमों के प्रयोजन के लिए उद्भव के देश या आयात करने वाले देश के बीच किया गया समझा जाएगा ।

6. (1) अन्वेषण का शुरु किया जाना—उपनियम (4) में यथा उपबंधित के सिवाय, अभिहित प्राधिकारी केवल घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किसी लिखित आवेदन की प्राप्ति पर अभिकथित महायिकी की विद्यमानता, मात्रा उसके प्रभाव को अवधारित करने के लिए अन्वेषण शुरू करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन उस प्रकृति में होगा जो अभिहित प्राधिकारी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें और आवेदन निम्नलिखित साक्ष्य द्वारा समर्थित होगा—

(क) महायिकी, और यदि संभव हो, इसकी रकम,

(ख) क्षति, जहां लागू हो, और

(ग) जहां लागू हों, वहां ऐसे महायिकी आदेशों और अभिकथित क्षति के बीच कारणत्मक संबंध ;

(3) अभिहित प्राधिकारी, उपनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन के अनुसरण में तब तक अन्वेषण शुरू नहीं करेगा, जब तक कि—

(क) वह वैसी ही वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों द्वारा व्यक्त आवेदन के समर्थन या उसके विरोध की माता की जांच के आधार पर यह अवधारित नहीं कर लेता कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया है।

परन्तु कोई अन्वेषण तब शुरू नहीं किया जाएगा जब आवेदन का अभिहिततः समर्थन करने वाला घरेलू उत्पादक, घरेलू उद्योग द्वारा वैसी ही उत्पाद के कुल उत्पादन के पचीस प्रतिशत से कम का लेना देता है, और

(ख) वह आवेदन में दिए गए साध्य का सम्पन्नता और पर्याप्तता की परीक्षा और अपना यह समाधान नहीं कर लेता है कि किसी अन्वेषण के शुरू किए जाने के न्यायोचित रहने के लिए—

(i) महायिकी

(ii) क्षति गणना, जहां लागू हो, और

(iii) जहां लागू हो, वहां ऐसे महायिकी आयातों और अभिकथित क्षति के बीच किसी कारणवश संबंध का, साध्य है।

स्पष्टीकरण :— इस नियम के प्रयोजन के लिए, आवेदन “घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से” किया गया समझा जाएगा, यदि आवेदन उन घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित है जिनका सामूहिक उत्पादन आवेदन का, यथास्थिति, समर्थन या विरोध प्रकट करने वाले घरेलू उद्योग के उस भाग द्वारा उत्पादित वैसी ही वस्तु के कुल उत्पादन के पचास प्रतिशत से अधिक है।

(4) उपनियम (1) में किसी बात के होने हुए भी, अभिहित प्राधिकारी कोई अन्वेषण स्वप्रेरणा से शुरू कर सकेगा यदि उसका सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन नियुक्त सीमा शुल्क कलक्टर से या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त जानकारी में यह समाधान हो जाता है कि उपनियम (3) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट परिस्थितियों की विद्यमानता के बारे में पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है।

(5) अभिहित प्राधिकारी, कोई अन्वेषण शुरू करने से पूर्व निर्यात करने वाले देश की सरकार को अधिसूचित करेगा।

7. अन्वेषणों को शासित करने वाले सिद्धान्त—(1) अभिहित प्राधिकारी किसी वस्तु की अभिकथित महायिकी की विद्यमानता माता और प्रभाव का अवधारण करने के लिए कोई अन्वेषण शुरू करने का विनिश्चय करने के पश्चात् अपना विनिश्चय अधिसूचित करे हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा। अन्वेषण शुरू किए जाने के संबंध में सार्वजनिक

सूचना के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त सूचना होगी—

(i) निर्यात करने वाले देश का नाम या देश और अन्तर्कलित वस्तु

(ii) अन्वेषण शुरू किए जाने की तारीख ;

(iii) महायिकी व्यवहार या अन्वेषण किए जाने वाले व्यवहारों का वर्णन ;

(iv) उन कारणों का सारांश जिन पर क्षति का अभि-
कथन आधारित है;

(v) वह पता जिन पर हितवद्ध देशों और हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अभ्यावेदन भेजे जाएंगे ; और

(vi) हितवद्ध देशों और हितवद्ध पक्षकारों को उनके दृष्टिकोण की जानकारी देने के लिए अनुज्ञात समय सीमा।

(2) सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अभिहित प्राधिकारी द्वारा अभिकथित महायिकी वस्तु के ज्ञात निर्यातकर्ताओं, निर्यात करने वाले सम्बद्ध देश की सरकार और अन्य हितवद्ध पक्षकारों को संप्रेषित की जाएगी।

(3) अभिहित प्राधिकारी, नियम 6 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की एक प्रति—

(i) ज्ञात निर्यातकर्ताओं या सम्बद्ध व्यापार संगम को, जब निर्यातकर्ताओं की संख्या अधिक हो ;

(ii) निर्यात करने वाले देश की सरकार को देगा ;

परन्तु वह निश्चित में अनुरोध किए जाने पर किसी अन्य हितवद्ध पक्षकार को भी आवेदन की एक प्रति उपलब्ध कराएगा।

(4) अभिहित प्राधिकारी निर्यातकर्ताओं, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितवद्ध देशों की सरकारों से ऐसे प्रश्न में जो उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए किसी जानकारी की अपेक्षा करने वाली सूचना जारी कर सकेगा और किसी जानकारी ऐसे व्यक्तियों द्वारा सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जैसी पर्याप्त कारण उपदर्शित किए जाने पर अभिहित प्राधिकारी अनुज्ञात करे, लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक सूचना और अन्य वस्तावेज उस तारीख में, जिसको वे वस्तावेज अभिहित प्राधिकारी द्वारा निर्यात करने वाले देश के सम्बन्धित राजनयिक प्रतिनिधि को भेजी गई थी या संप्रेषित की गई थी, एक सप्ताह के भीतर प्राप्त की गई समझी जाएगी।

(5) अभिहित प्राधिकारी अन्वेषण के अधीन वस्तु के औद्योगिक उपयोगताओं और जहाँ वस्तु पुटकर स्तर पर सामान रूप में विक्रीत की जाती है वहाँ प्रतिनिधि उप-भोक्ता संगठनों को ऐसी जानकारी देने का अवसर भी प्रदान करेगा जो साहायिकी और जहाँ लागू हो क्षति और कारणात्मकता की बाबत अन्वेषण के लिए सुसंगत है।

(6) अभिहित प्राधिकारी, किसी हितबद्ध देश या किसी हितबद्ध पक्षकार या उसके प्रतिनिधि को अन्वेषण में सुसंगत जानकारी मौखिक रूप से भी अनुज्ञात करेगा किन्तु ऐसी मौखिक जानकारी पर तब विचार किया जाएगा जब वह तत्पश्चात् लिखित रूप से पुनः प्रस्तुत की जाए।

(7) अभिहित प्राधिकारी एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को अन्वेषण में भाग ले रहे अन्य हितबद्ध पक्षकार को उपलब्ध कराएगा।

(8) उस मामले में जहाँ कोई हितबद्ध पक्षकार युक्ति-युक्त कालावधि के भीतर आवश्यक जानकारी के लिए पट्टेच से इन्कार करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं करता है, या अन्वेषण में अत्यधिक अड़चन डालता है, वहाँ अभिहित प्राधिकारी उसकी उपलब्ध जानकारी के आधार पर अपने निष्कर्ष अलिखित करेगा और केंद्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें करेगा जो वह ऐसी परिस्थितियों के अधीन ठीक समझे।

8. गोपनीय जानकारी :- (1) नियम 7 के उपनियम (1), उपनियम (3) और उपनियम (7), नियम 14 के उपनियम (2), नियम 17 के उपनियम (4) और नियम 19 के उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी नियम के उपनियम (1) के अधीन प्राप्त आवेदनों की प्रतियाँ या अन्वेषण के अनुक्रम में किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर अभिहित प्राधिकारी को दी गई कोई अन्य जानकारी, अभिहित प्राधिकारी का उसकी गोपनीयता के बारे में समाधान हो जाने पर उसके द्वारा उसे गोपनीय माना जाएगा और ऐसी कोई जानकारी, ऐसी जानकारी देने वाले पक्षकार के विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) अभिहित प्राधिकारी, गोपनीय आधार पर जानकारी देने वाले पक्षकारों से गोपनीय जानकारी के सार का युक्ति-युक्त बोध अनुज्ञात करने के लिए पर्याप्त विस्तार से उसका अगोपनीय सारांश देने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि, किसी पक्षकार की राय में, ऐसी जानकारी का सारांश नहीं बताया जा सकता है तो ऐसा पक्षकार अभिहित प्राधिकारी को ऐसे कारणों का एक कथन प्रस्तुत कर सकेगा कि उसका सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है।

(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि अभिहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध अपेक्षित नहीं है या जानकारी देने वाला जानकारी को सर्वाविदित करने या साधारण या संक्षिप्त रूप में उसका प्रकटन प्राधिकृत करने के लिए, इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी जानकारी का अवहेलना कर सकेगा।

9. जानकारी की यथार्थता :- नियम 7 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट मामलों के सिवाय अभिहित प्राधिकारी अन्वेषण के अनुक्रम के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदाय की गई जानकारी की यथार्थता के बारे में अपना यह समाधान करेगा जिस पर इसके निष्कर्ष आधारित है।

10. अन्य विनिर्दिष्ट देशों के राज्य क्षेत्र में अन्वेषण :-

(1) यदि अभिहित प्राधिकारी, दी गई जानकारी का सत्यापन करने के लिए अतिरिक्त व्योरे प्राप्त करने के लिए अन्य देशों के राज्य क्षेत्रों में अन्वेषण करेगा :

परंतु यह तब जब कि अभिहित प्राधिकारी ऐसे देश को पहले से अधिमूर्चित करना है और ऐसा देश ऐसे अन्वेषण पर आपत्ति नहीं करता है। (2) अभिहित प्राधिकारी किसी वाणिज्यिक संगठन के परिसर का भी अन्वेषण कर सकेगा और यदि ऐसा संगठन सहमत होता है तो वह उसके अभिलेखों की परीक्षा कर सकेगा तथा यदि वह देश जिसके राज्य क्षेत्र में उक्त वाणिज्यिक संगठन स्थित है, अधिमूर्चित है, और उसने ऐसे अन्वेषण के संचालन के लिए कोई आपत्ति नहीं की है।

11. साहायिकी की प्रकृति : (1) अभिहित प्राधिकारी साहायिकी का अवधारण करते समय, यह अभिनिश्चित करेगा कि क्या अन्वेषणाधीन साहायिकी :-

- (क) निर्यात पालन से संबंधित है या
- (ख) देशी माल का निर्यात वस्तु में आयातित माल के उपयोग से संबंधित है, या
- (ग) यह वस्तु का विनिर्माण करने, उत्पादन करने या निर्यात करने में लगे सीमित संख्या में व्यक्तियों को प्रदत्त की गई है, जब तक कि ऐसी साहायिकी—
 - (i) विनिर्माण उत्पादन या निर्यात में लगे व्यक्तियों द्वारा या उनकी ओर से किए जाने वाले अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए न हो ; या
 - (ii) निर्यात करने वाले देश के राज्य क्षेत्र के भीतर अलाभप्रद क्षेत्रों की सहायता के लिए न हो, या
 - (iii) नई पर्यावरणीय अपेक्षाओं की विद्यमान मुविधाओं के अंगीकरण का संबन्धन करने के लिए सहायता के लिए न हो :

परंतु उपखंड (क) और उपखंड (ख) के प्रयोजनों के लिए बहुपक्षीय व्यापार वार्ता, उस्वे चक्र के अंतिम ऐक्ट में अंतर्विष्ट कृपि करार में उल्लिखित प्रकार की साहायिकियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : (1) खंड के उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए "अनुसंधान क्रियाकलाप के लिए साहायिकी" पद से वाणिज्यिक संगठनों या उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान

स्थापनों द्वारा वाणिज्यिक संगठनों के साथ संबंध के आधार पर किए गए अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए सहायता अभिप्रेत होगी, यदि सहायता के अनर्गत औद्योगिक अनुसंधान की लागत के पचहत्तर प्रतिशत या पूर्व प्रतियोगी विकास क्रियाकलाप की लागत के पचास प्रतिशत से अधिक है और परंतु यह तब जब कि ऐसी सहायता अन्य रूप से निम्नलिखित तक सीमित है :-

- (i) कार्मिक (अनुसंधान क्रियाकलाप के अन्य रूप से नियोजित अनुसंधानकर्ताओं तकनीशियनों और अन्य सहायक कर्मचारिवृन्द) की लागत ;
- (ii) अनुसंधान क्रियाकलाप के लिए अन्य रूप में और स्थायी रूप से प्रयुक्त उपकरणों, उपकरणों, भूमि और भवनों की लागत तब के सिवाय जब वाणिज्यिक आधार पर व्ययन किया जाए ;
- (iii) अनुसंधान क्रियाकलाप के लिए अन्य रूप से प्रयुक्त परामर्शी और समनुव्य सेवाओं की लागत, जिनके अनर्गत क्य किया गया अनुसंधान तकनीकी ज्ञान, पेटेंट, आदि है ।
- (iv) अनुसंधान क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप प्रत्यक्षतः उपगत अतिरिक्त ऊपरी लागत ;
- (v) अनुसंधान क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप प्रत्यक्षतः उपगत अन्य परिचालन लागत (जैसे सामग्री, प्रदाय और बैमी ही लागत) ।

(2) खंड (ग) के उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, "अलाभप्रद क्षेत्रों की सहायता के लिए साहायिकी" पद से निर्धारित करने वाले देश के राज्य क्षेत्र के भीतर अलाभप्रद क्षेत्रों को क्षेत्रीय विकास के क्षेत्र साधारण ढांचे के अनुसरण में दी गई सहायता अभिप्रेत है और ऐसी साहायिकी पात्र क्षेत्र के भीतर सीमित संख्या में उद्यमों को प्रदान नहीं की गई है : परंतु यह तब जब कि-

- (i) प्रत्येक अलाभप्रद क्षेत्र स्पष्टरूप से अभिहित स्पर्श-जन्य भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, जिसकी भाष्य आर्थिक और प्रशासनिक पहचान हो;
- (ii) क्षेत्र को उन तटस्थ और वस्तुपूरक मानदंडों के आधार पर अलाभप्रद समझा जाता है जिनमें यह उपदर्शित किया गया है कि क्षेत्र की कठिनाइयाँ अस्थायी परिस्थितियों के अलावा उद्भूत होती है : ऐसे मानदंड विधि, विनियम या अन्य शासकीय दस्तावेज में स्पष्टतः परिभाषित किए जाने चाहिए जिसमें कि उनका स्थापन किया जा सके ;
- (iii) मानदंडों के अंतर्गत आर्थिक विकास का एक मापन भी होगा जो निम्नलिखित बातों में से कम से कम एक बात पर आधारित होगा :-

- (i) प्रतिव्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति घरेलू आय, या प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन

में से एक, जो संबंध राज्य क्षेत्र के लिए औसत के पचासी प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए;

- (ii) बेरोजगारी दर, जो संबंध राज्य क्षेत्र के लिए औसत की कम से कम एक सी दस प्रतिशत होनी चाहिए,

तथापि, तीन वर्ष की अवधि के लिए किए गए माप के अनुसार ऐसा मापन मिश्रित हो सकेगा और उसके अंतर्गत अन्य बातें भी हो सकती हैं ।

(3) खंड (ग) के उपखंड के प्रयोजनों के लिए,

"नई पर्यावरणीय अपेक्षाओं की विश्व मान सुविधाओं के अंगीकरण का संबंधन करने के लिए साहायिकी" से विधि और/या विनियमों द्वारा प्रतिरूपित नई पर्यावरणीय अपेक्षाओं की विश्वमान सुविधाओं के अंगीकरण का संबंधन करने के लिए, सहायता अभिप्रेत है जिस के परिणामस्वरूप व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अत्यधिक दबाव और वित्तीय बोझ पड़ता है :-

परंतु सहायता :- (i) एक समय में किया गया अनावर्तनीय उपाय है ; और

(ii) अंगीकरण लागत के 20 प्रतिशत तक सीमित है; और

(iii) सहायता दिए गए विनिधान के प्रतिस्थापन और परिचालन लागत के अनर्गत नहीं आती है, जिसका वहन पूर्णतया व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाना चाहिए ; और

(iv) किसी फर्म के ल्यूसेंस और प्रदूषण में योजनागत कमी करने से सीधे जुड़ी है और उसके अनुपात में है तथा इसके अनर्गत कोई विनिर्माण लागत बचत नहीं है जो प्राप्त की जा सकती हो ; और

(v) ऐसी सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उपलब्ध है जो नए उपस्कर और/या उत्पादन प्रक्रियाओं को अंगीकार कर सकते हैं ।

(4) अभिहित प्राधिकारी, उपनियम (1) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकार की साहायिकी का अवधारणा करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, इन नियमों के उपाबंध 2 में अधिकृत सिद्धांतों का विचार में लेगा ।

12. फायदा प्रदान करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत :- अभिहित प्राधिकारी, किसी साहायिकी के अनुसरण में, प्राप्ति-कर्ता को फायदा प्रदान करने का अवधारणा करते समय, निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा :-

- (क) साधारण पूंजी की सरकारी के व्यवस्था पर लाभ प्रदान करने के रूप में तब तक विचार नहीं किया जाएगा तब तक विनिधान विनिश्चय को अनुसृत करने वाले देश के राज्य क्षेत्र में प्राइवेट विनिधान

कर्माओं की प्राथिक विनिधान व्यवहार (जिसके अंतर्गत जोखिम पूँजी के लिए व्यवस्था भी है) से असंगत नहीं माना जा सकता है।

(ख) सरकार द्वारा दिया गया कोई ऋण लाभ प्रदान करने वाला तब तक नहीं माना जाएगा जब तक ऐसी रकम, जो ऋण प्राप्त करने वाला व्यावसायिक प्रतिष्ठान सरकारी ऋण पर संदाय करती है और ऐसी रकम अंतर जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान ऐसे सदृश वाणिज्यिक ऋण पर, जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठान वास्तव में बाजार में प्राप्त कर सकता था, संदाय करेगी, के बीच अंतर नहीं है ;

(ग) सरकार द्वारा दी गयी कोई ऋण गारंटी तब तक फायदा प्रदान करने वाली नहीं मानी जाएगी जब तक ऐसी रकम, जो गारंटी प्राप्त करने वाला व्यावसायिक प्रतिष्ठान सरकारी गारंटीकृत किसी ऋण पर संदाय करती है और ऐसी रकम, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान सरकारी गारंटी के न होने पर किसी सदृश वाणिज्यिक ऋण पर संदाय करेगी, के बीच अंतर न हो। इस दशा में फायदा फीसों में किसी अंतर के लिए समायोजित इन दोनों रकमों के बीच का अंतर होगा ;

(घ) सरकार द्वारा माल या सेवाओं या माल के क्रय से संबंधित व्यवस्था तब तक फायदा प्रदान करने वाली नहीं मानी जाएगी जब तक व्यवस्था पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए न की गई हो, या क्रय पर्याप्त पारिश्रमिक से अधिक के लिए न किया गया हो। पारिश्रमिक की पर्याप्तता का अवधारण व्यवस्था या क्रय (जिसके अंतर्गत कोमत, खानिटी उपलब्धता परिवहन और क्रय या विक्रय की अन्य शर्तें भी हैं) करने वाले देश में प्रचलित माल या सेवा के लिए विद्यमान बाजार दशाओं के संबंध में किया जाएगा।

13. क्षति का अवधारण (1) विनिर्दिष्ट देशों में आयातों के मामले में अभिहित प्राधिकारी यह भी निष्कर्ष देगा कि ऐसी वस्तु का भारत में, आयात किए जाने से भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचती है या उससे भारत में किसी उद्योग की स्थापना का तात्त्विक गतिरोध उत्पन्न होता है।

(2) उपनियम (3) के अधीन निष्कर्षित क्षति के विषय, अभिहित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ नियम के उपाबंध 1 में अधिव्यक्ति सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, किसी उद्योग की स्थापना की क्षति, क्षति की आशंका, तात्त्विक गतिरोध और साहायिकी आयातों और क्षति के बीच कारण संबंध का अवधारण करेगा।

(3) अभिहित प्राधिकारी, अवधारण मामलों में, क्षति की विद्यमानता के बारे में इस बात के होते हुए भी

निष्कर्ष दे सकेगा कि घरेलू उद्योग के पर्याप्त भाग को क्षति नहीं है, यदि :—

(1) साहायिकी आयातों का किसी एकल बाजार में सकेन्द्रण है, और

(2) साहायिकी आयात ऐसे बाजार के भीतर सभी या लगभग सभी उत्पादन के सभी उत्पादकों को क्षति पहुंचा रहे हैं।

14. प्रारंभिक निष्कर्ष (1) अभिहित प्राधिकारी, अन्वेषण करने के लिए शीघ्रता से कार्यवाही करेगा और समुचित मामलों में, किसी साहायिकी के अस्तित्व और उसके स्वरूप के बारे में तथा विनिर्दिष्ट देशों में आयातों की वास्तविक प्रारंभिक निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में भी अपने प्रारंभिक निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और ऐसे निष्कर्ष में साहायिकी के अस्तित्व और क्षति संबंधी प्रारंभिक अवधारणा के लिए पर्याप्त रूप से विस्तृत स्पष्टीकरण होगा और तथ्य तथा विधि के उन विषयों के प्रति, जिनके कारण स्वीकार या अस्वीकार किए जाने के बारे में बहस हुई, निर्देश करेगा।

ऐसे निष्कर्ष में निम्नलिखित होगा :—

(1) प्रदायकर्ताओं के या जब यह माध्य न हो तो, प्रदाय करने में लगे देशों के नाम ;

(2) उत्पाद का वर्णन, जो सीमाशुल्क प्रयोजनों के लिए पर्याप्त है।

(3) स्थापित की गई साहायिकी की रकम और वह आधार जिसमें विद्यमान साहायिकी अवधारित की गई है।

(4) क्षति अवधारण से सुसंगत प्रतिकूल; और

(5) अवधारण प्रारंभ करने के मुख्य कारण।

(2) अभिहित प्राधिकारी अपने प्रारंभिक निष्कर्षों को अभिलिखित करने के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा।

15. अन्तिम शुल्क का उदग्रहण :—केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार, अभिहित प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर अन्तिम शुल्क अधिरोपित कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई शुल्क अभिहित प्राधिकारी द्वारा अन्वेषणों के प्रारंभ करने के अपने विनिश्चय की सार्वजनिक सूचना के जारी करने की तारीख से साठ दिन की समाप्ति से पूर्व, अधिरोपित नहीं किया जाएगा ;

परन्तु यह और कि ऐसा शुल्क चार मास में अनधिक अवधि के लिए ही प्रवृत्त रहेगा।

16. अन्वेषण की समाप्ति (1) अभिहित प्राधिकारी, लोक सूचना जारी करके किंवा अन्वेषण को तुरन्त समाप्त कर सकेगा :—

- (क) यदि वह प्रभावित घरेलू उद्योग में : जिसके लिए अन्वेषण प्रारंभ किया गया था या उसकी ओर से लिखित रूप में ऐसा करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त करता है ;
- (ख) अन्वेषण के अनुक्रम में यह समाधान हो जाता है कि महाधिकारी देने का या जहां लागू हो, अन्वेषण जारी रखना न्यायोचित ठहराने के लिए क्षति का कोई पर्याप्त साध्य नहीं है ;
- (ग) यदि वह यह अवधारित करता है कि महाधिकारी की रकम मूल्यानुसार एक प्रतिशत से कम है या ऐसी किसी वस्तु की दशा में जो किसी विकासशील देश में प्रारंभ होती है, वह मूल्यानुसार दो प्रतिशत से कम है, या
- (घ) यदि वह यह अभिधारित करता है कि महाधिकारी-कृत आयात की मात्रा, चाहे वह अभिधारित करता हो या सभाविक या क्षति, जहां लागू हो नगण्य है या कि फिर किसी विकासशील देश में उत्पन्न किसी उत्पाद की दशा में, सहायता प्राप्त आयातों की मात्रा भारत में तत्तमान उत्पाद के कुल आयात के चार प्रतिशत से कम है, जब तक ऐसे विकासशील देश में आयात जिसके कुल आयात का अपना अंश सामूहिक रूप से चार प्रतिशत से कम है, भारत में वैसे ही उत्पाद के कुल आयात के नौ प्रतिशत से अधिक न होता हो।

17. कीमत का वचनबंध स्वीकार करने पर अन्वेषण का निलम्बन या समाप्ति—(1) अभिहित प्राधिकारी किसी अन्वेषण को निलम्बित या समाप्त कर सकेगा,

(क) यदि निर्यात करने वाले देश की सरकार :—

- (1) यह वचनबंध प्रस्तुत करती है कि वह महाधिकारी बाधित ले लेगी।
- (2) विनिर्दिष्ट देशों की दशा में युक्तियुक्त समय के भीतर माहाधिकारी की मात्रा को परिसीमित करने या ऐसी माहाधिकारी के प्रभाव को दूर करने के लिए अन्य उपयुक्त उपाय करने का वचनबंध करती है, परन्तु यह तब जब कि अभिहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि माहाधिकारी का हानिकारक प्रभाव समाप्त हो गया है, अथवा

(ख) विनिर्दिष्ट देशों की दशा में, सबूत निर्यातक अपने कीमतों को पुनरीक्षित करने का वचनबंध करता है ताकि माहाधिकारी का हानिकारक प्रभाव दूर किया जा

सके और अभिहित प्राधिकारी का दूर किया जा सके और अभिहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि माहाधिकारी का हानिकारक प्रभाव समाप्त हो गया है :

परन्तु यह तब जब कि इस खंड के परिणामस्वरूप, कीमत में कोई वृद्धि उससे अधिक नहीं है जो माहाधिकारी की मात्रा को समाप्त करने के लिए आवश्यक है ;

परन्तु यह भी कि अभिहित प्राधिकारी यदि केन्द्रीय सरकार वादा करे या निर्धारित करने वाला देश ऐसा विनिश्चय करे तो, अन्वेषण को पूरा करेगा।

(2) (1) उपनियम (1) के अधीन कीमत वृद्धि में संबंधित कोई वचनबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि अभिहित प्राधिकारी ने माहाधिकारी और क्षति का आंशिक अवधारण नहीं किया हो ;

परन्तु किसी निर्यातकर्ता ने कोई वचनबंध निर्यातकर्ता से केवल तब स्वीकार किया जाएगा जब अभिहित प्राधिकारी ने निर्यातकर्ता देश में सहमति अभिप्राप्त कर ली हो।

(3) अभिहित प्राधिकारी, किसी देश या निर्यातकर्ता द्वारा प्रस्थापित ऐसे वचनबंध भी स्वीकार नहीं कर सकेगा, यदि वह ऐसे वचनबंध के स्वीकार किए जाने को किसी अन्य कारण से असह्य या अस्वीकार्य समझता है।

(4) अभिहित प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार को किसी वचनबंध के स्वीकार किए जाने और अन्वेषण के निलम्बन या समाप्ति के बारे में सूचना देगा और इस संबंध में मार्ग-निर्देश सूचना भी जारी करेगा। मार्ग-निर्देश सूचना में, अन्य बातों के साथ-साथ, वचनबंध का अगोपनीय भाग होगा।

(5) ऐसे मामलों में, जहां अभिहित प्राधिकारी द्वारा कोई वचनबंध स्वीकार कर लिया गया है, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 9 क की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अवधि के लिए जब तक अभिहित प्राधिकारी को स्वीकार्य वचनबंध विधिमार्ग रहता है, शुल्क अधिरोपित नहीं कर सकेगी।

(6) जहां अभिहित प्राधिकारी ने उपनियम (1) के अधीन कोई वचनबंध स्वीकार किया है, वहां वह निर्यातकर्ता देश से या वहां ऐसे निर्यातकर्ता से, जिसमें ऐसा वचनबंध स्वीकार किया गया है, वचनबंध के पूरा किए जाने से सुसंगत जानकारी समय-समय पर, उपलब्ध कराने और सुसंगत आंकड़ों का सत्यापन अनुमान करने की अपेक्षा कर सकेगा : परन्तु किसी वचनबंध के किसी अतिक्रमण की दशा में, अभिहित प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार को सूचित करेगा और अन्वेषण को शीघ्र पूरा करेगा।

(7) अभिहित प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से या प्रश्नगत वस्तु के निर्यातकर्ताओं या आयातकर्ताओं से या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति या से प्राप्त किसी अनुरोध के आधार पर, पहले दिए गए किसी वचनबंध को जारी रखने की आवश्यकता का समय-समय पर पुनर्विचार करेगा।

18. जानकारी का प्रकटीकरण :—अभिहित प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों को देने से पूर्व ऐसे विचाराधीन आवश्यक तथ्यों के बारे में जो उसके विनिश्चय के आधार बनते हैं,

सभी हितबद्ध पक्षकारों और हितबद्ध देशों को सूचित करेगा और हितबद्ध पक्षकारों को उनके हितों की प्रतिरक्षा के लिए अनुज्ञान करेगा ।

19. अंतिम निष्कर्ष :- (1) अभिहित प्राधिकारी, किसी अन्वेषण के प्रारंभ किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, यह अवधारित करेगा कि अन्वेषण के अधीन वस्तु साहायिकी दी जा रही या नहीं और केन्द्रीय सरकार को,

(क) निम्नलिखित के बारे में अपने अंतिम निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा—

- (i) अन्वेषण के अधीन वस्तु की बाबत दी जा रही साहायिकी का स्वरूप और ऐसी साहायिकी की मात्रा ;
- (ii) विनिर्दिष्ट देशों में आयातों की दशा में, क्या वस्तु का भारत में आयात किए जाने से, भारत में स्थापित उद्योग को तात्त्विक क्षति होती है या होने की आशंका है या भारत में किसी उद्योग की स्थापना और साहायिकी प्राप्त आयात तथा ऐसी क्षति के बीच कारण संबंध में तात्त्विक रूप में गतिरोध उत्पन्न होता है ;
- (iii) क्या भूत लक्षी उद्ग्रहण की मांग की जाती है और यदि हाँ तो, उनके लिए कारण और ऐसे उद्ग्रहण के प्रारंभ की तारीख :

(ख) शुल्क की ऐसी रकम की भिन्नता जो यदि उद्ग्रहीत की जाती तो, घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होती :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, आपत्ताधिक प्रकृति की परिस्थितियों में एक वर्ष की पूर्ववर्ति अवधि को छह मास तक और बढ़ा सकेगी :

परन्तु यह और कि उन मामलों में, जहाँ अभिहित प्राधिकारी ने नियम 17 में यथा उपबंधित किसी कीमत वचनबंध के स्वीकार किए जाने पर अन्वेषण को निलम्बित कर दिया है और तत्पश्चात् उक्त वचनबंध के निबंधनों का अतिक्रमण होने पर उसे फिर से प्रारंभ करता है, वहाँ उस अवधि को जिस तक अन्वेषण को निलम्बनाधीन रखा गया था, उक्त एक वर्ष की अवधि की संगणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

(2) यदि अंतिम निष्कर्ष सकरात्मक है, तो उसमें तथ्यों और विधि के विषय पर ऐसी सभी जानकारी और कारण अंतर्विष्ट होंगे, जिनसे निष्कर्ष निकाला गया है, और उसमें निम्नलिखित के बारे में भी सूचना होगी :-

- (i) प्रदाय कर्तव्यों के या जब यह प्रसाध्य हो तो प्रदाय करने वाले देशों के नाम ;

(ii) उत्पाद का वर्णन, जो सीमाशुल्क प्रयोजनों के लिए पर्याप्त है ;

(iii) स्थापित साहायिकी की रकम और वह आधार जिसमें साहायिकी का अस्तित्व अवधारित किया गया है ;

(iv) क्षति अवधारण से सुसंगत प्रतिकूल ,

(v) अवधारण प्रारंभ करने के मुख्य कारण ।

(3) अभिहित प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा ।

20. शुल्क का उद्ग्रहण :- (1) केन्द्रीय सरकार, अभिहित प्राधिकारी, द्वारा नियम 19 के अधीन अंतिम निष्कर्षों के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर, अंतिम निष्कर्ष के अधीन आने वाली वस्तु का भारत में आयात करने पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा प्रतिशुल्क अधिरोपित कर सकेगी, जो अभिहित प्राधिकारी द्वारा नियम 19 के अधीन यथा अवधारित साहायिकी की रकम से अधिक न हो :

परन्तु विनिर्दिष्ट देशों में आयातों की दशा में, शुल्क की रकम उस रकम से, जो घरेलू उद्योग में हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त पाई गई है, अधिक नहीं होगी ।

(2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी घरेलू उद्योग का निर्वहन नियम 2 के उपखंड (ख) के परन्तुक के अनुसार किया गया है, वहाँ निर्यातकर्ता को सम्बद्ध क्षेत्र में साहायिकी कीमत पर निर्यात बंद करने का अवसर देने के पश्चात् या नियम 17 के अनुमरण में अन्यथा वचनबंध देने के पश्चात् ही प्रति शुल्क उद्ग्रहीत किया जाएगा और ऐसे मामलों में जहाँ ऐसा वचनबंध तत्पश्चात् में नहीं दिया गया है वहाँ केवल ऐसे विनिर्दिष्ट उत्पादकों के, जो प्रथमतः क्षेत्र में प्रदाय करते हैं, उत्पादन पर शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया जा सकता

(3) यदि अभिहित प्राधिकारी का अंतिम निष्कर्ष नकारात्मक है, अर्थात् वह ऐसे प्रथमदृष्ट्या साध्य के प्रतिकूल है, जिसके आधार पर अन्वेषण पर प्रारंभ किया गया था, तो केन्द्रीय सरकार, अभिहित प्राधिकारी द्वारा नियम 19 के अधीन अंतिम निष्कर्षों के प्रकाशन के पैंतालीस दिन के भीतर, अधिरोपित किया गया अंतिम शुल्क, यदि कोई हो, वापस ले लेगी ।

21. अविभेदकारी आधार पर शुल्क का अधिरोपण— नियम 15 या नियम 20 के अधीन अधिरोपित कोई "प्रतिशुल्क अविभेदकारी आधार पर होगा और ऐसी वस्तु के सभी आयातों को, जिन्हें साहायिकी प्राप्त पाया और जहाँ लागू हो, क्षति कारित करती हों, सिवाय उन स्रोतों में आयातों की दशा में, जिनसे नियम 11 के निबंधनों के अनुसार वचनबंध स्वीकार किया गया है, लागू होगा ।

22. शुल्क का प्रारम्भ :- (1) नियम 15 और नियम 20 के अधीन उद्गृहीत प्रतिशुल्क अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी,-

(क) जहाँ कोई "अन्तिम शुल्क उद्गृहीत किया गया है और जहाँ अभिहित प्राधिकारी ने क्षति का कोई निष्कर्ष अभिलिखित किया है या जहाँ अभिहित प्राधिकारी ने क्षति होने की आशंका निष्कर्ष अभिलिखित किया है और आगे यह निष्कर्ष है कि अन्तिम शुल्क के अभाव में साहायिकी आयातों के प्रभाव के कारण क्षति होगी, वहाँ प्रतिशुल्क, अन्तिम शुल्क के अधिरोपण की तारीख से अधिरोपित किया जा सकेगा।

(ख) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, प्रतिशुल्क ऐसे अन्तिम शुल्क के अधिरोपण के पूर्व नब्बे दिन के प्रारंभ की तारीख से भूतलक्षी रूप से उद्गृहीत किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि नियम 17 के उपनियम (6) में निर्दिष्ट कीमत बचनबंध के अतिक्रमण के मामले में कोई शुल्क ऐसे आयातों पर, जो बचनबंध के निबंधनों के अतिक्रमण से पहले देशी उपभोग के लिए किए गए हैं, भूतलक्षी रूप से उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

23. शुल्क का प्रतिदाय : (1) यदि अभिहित प्राधिकारी द्वारा किए गए अन्वेषण के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित प्रतिशुल्क, पहले से अधिरोपित और संगृहीत अन्तिम शुल्क से अधिक है तो आयातकर्ता से अन्तर का संग्रहण नहीं किया जाएगा।

(2) यदि अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात् नियत प्रतिशुल्क पहले ही अधिरोपित और संगृहीत अन्तिम शुल्क से कम है, तो अन्तर को आयातकर्ता को वापस कर दिया जाएगा।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम 18 के उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित अन्तिम शुल्क वापस ले लिया गया है, तो पहले ही अधिरोपित और संगृहीत अन्तिम शुल्क, यदि कोई हो, आयातकर्ता को वापस कर दिया जाएगा।

24. पुनर्विलोकन :- (1) अभिहित प्राधिकारी, समय समय पर, प्रतिशुल्क के निरन्तर अधिरोपण की आवश्यकता का पुनर्विलोकन करेगा और यदि उसके द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के निरन्तर अधिरोपण के लिए कोई न्यायोचित्य नहीं है, तो वह केन्द्रीय सरकार से उसके वापस किए जाने के लिए सिफारिश करेगा।

4 GI/95-2

(2) उपनियम (2) के अधीन प्रारंभ किया गया कोई पुनर्विलोकन ऐसे पुनर्विलोकन के प्रारंभ की तारीख से बारह मास से अनधिक अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

(3) नियम 6, 7, नियम 8, नियम 9, नियम 10, नियम 11, नियम 12, नियम 13, नियम 16, नियम 17, नियम 18, नियम 19, नियम 20, नियम 22 और नियम 23 के उपबंध, पुनर्विलोकन के मामले में यथा-आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

उपाबंध

क्षति अवधारित करने को शासित करने वाले सिद्धान्त अभिहित प्राधिकारी क्षति का अवधारण करने समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखेगा :-

1. (1) सार्वक साक्ष्य पर आधारित नियम के प्रयोजनों के लिए क्षति के अवधारण में (क) साहायिकी प्राप्त आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में वैसे ही उत्पाद की कीमतों पर साहायिकी प्राप्त आयात के प्रभाव और (ख) ऐसे उत्पादों पर उन आयातों के पारिणामिक प्रभाव, दोनों की वस्तुपरक परीक्षा अंतर्बलित होगी।

(2) साहायिकी प्राप्त आयातों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, अभिहित प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर विचार करेगा कि क्या साहायिकी प्राप्त आयात में, आत्यंतिक रूप से या आयात करने वाले सदस्य उत्पादन या उपभोग के सापेक्ष में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

(3) कीमतों पर साहायिकी प्राप्त आयात के प्रभाव के संबंध में अभिहित प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या भारत में तत्समान उत्पाद की कीमत की तुलना में साहायिकी प्राप्त आयातों से कीमत में महत्वपूर्ण रूप से कमी हुई है या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा रूप से कीमतों की महत्वपूर्ण मात्रा तक घटाना या कीमत में ऐसी वृद्धि की जो अन्यथा हुई होती, महत्वपूर्ण मात्रा तक रोकना है।

(4) जहाँ एक से अधिक देशों में किसी उत्पाद के आयात समसामयिक रूप से प्रतिशुल्क जांच के अधीन हैं, वहाँ अभिहित प्राधिकारी उक्त आयात का संयोजी निर्धारण कर सकेगा यदि वह यह अवधारित करे कि-

(क) प्रत्येक देश से आयात की जाबत स्थापित साहायिकी मूल्यानुसार एक प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से किए गए आयात की मात्रा नगण्य नहीं है, और

(ख) आयातित उत्पाद और तत्समान देशी उत्पाद के बीच प्रतियोगिता की शर्तों को ध्यान में रखते हुए आयात के प्रभाव का संयोजी निर्धारण समुचित है।

(5) अभिहित प्राधिकारी संबंधित घरेलू उद्योग पर साहायिकी प्राप्त आयातों के प्रभाव की परीक्षा करते समय उन सभी सुसंगत आर्थिक कारकों और सूचकों का मूल्यांकन को सम्मिलित करेगा जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जिनके अन्तर्गत उत्पादन, विक्रय बाजार शेयर लाभ, उत्पादकता, निवेश पर लाभार्जन या क्षमता की उपयोगिता में प्राकृतिक और संभाव्य गिरावट, देशी कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, साहायिकी अन्तर का परिणाम, नकद प्रवाह सामान सूचियों, नियोजन, मजदूरी, उत्पादन, पूँजी या निवेश बढ़ाने की योग्यता पर वास्तविक और संभाव्य नकारात्मक प्रभाव भी है और कृषि के मामले में क्या सरकारी समर्थन वाले कार्यक्रमों पर भार में अभिवृद्धि हुई है।

2. संबंध-कारण—(1) यह अवश्य ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि साहायिकी प्राप्त आयात साहायिकी के प्रभावों के कारण क्षति कारित कर रहे हैं। साहायिकी आयातों और घरेलू उद्योग को भी क्षति के बीच कारण संबंध का प्रदर्शन, अभिहित प्राधिकारी के समक्ष सभी सुसंगत साक्ष्य की परीक्षा पर आधारित होगा। अभिहित प्राधिकारी साहायिकी प्राप्त आयात से भिन्न किन्हीं ऐसे ज्ञात कारकों की भी परीक्षा करेगा जो उसके साथ-साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, और इन अन्य कारकों द्वारा कारित क्षति साहायिकी प्राप्त आयातों के फलस्वरूप हुई नहीं मानी जानी चाहिए। ऐसे में जो इस संबंध में सुसंगत, अन्य बातों के साथ-साथ प्रसंगगत उत्पाद के गैर साहायिकी प्राप्त आयातों की माता और कीमतें, मांग में सकृचन या उपभोग की पद्धतियों में परिवर्तन, विदेशी और देशी उत्पादकों के अवरोधक व्यवहारिक व्यवहार और उनके बीच प्रतियोगिता, प्रौद्योगिकी और निर्यात सम्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता में विकास भी सम्मिलित है।

(2) साहायिकी प्राप्त आयातों के प्रभाव का निर्धारण तत्समान उत्पाद के घरेलू उत्पादन के संबंध में तब किया जाएगा जब उपलब्ध आंकड़ों से ऐसी कसौटियों, जैसे उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादकों के विक्रय और लाभ के आधार पर उस उत्पादन की पृथक पहचान की जा सकती हो। यदि उस उत्पादन की ऐसी पृथक पहचान संभव नहीं है, तो साहायिकी प्राप्त आयातों के प्रभाव का निर्धारण, ऐसे उत्पादों के, जिनके अन्तर्गत तत्समान उत्पाद भी हैं जिनके लिए आवश्यक जानकारी दी जा सकती है, निकटतम समूह या रेंज के उत्पादन की परीक्षा करके किया जाएगा।

3. तारिखिक क्षति की आशंका—तारिखिक क्षति के खतरे का अवधारण, तथ्यों पर न कि मात्र अभिकल्पना कल्पना या दूरस्थ संभाव्यता पर आधारित होगा। परिस्थितियों के ऐसे परिवर्तन की जिससे साहायिकी से क्षति कारित होने की स्थिति उत्पन्न होगी, स्पष्टतः पूर्वकल्पना की जानी चाहिए और वह परिवर्तन आसन्न होना चाहिए। तारिखिक क्षति के किसी खतरे की विद्यमानता के संबंध में अवधारण करते समय अभिहित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ इन कारकों पर विचार करेगा जैसे: (i) प्रसंगगत साहायिकी या

साहायिकियों की प्रकृति और उनसे उत्पन्न होने वाले व्यवसायिक प्रभाव; (ii)

(ii) घरेलू बाजार में साहायिकी प्राप्त आयातों की दर में ऐसी महत्वपूर्ण वृद्धि, जिससे पर्याप्त रूप में बढ़े हुए आयात की संभावना उपदर्शित होती हो;

(iii) निर्यातकर्ता की पर्याप्ततः निर्वाध रूप से, व्ययन योग्य क्षमता या इसकी क्षमता में आसन्न सारवान वृद्धि जिसने किन्हीं अतिरिक्त निर्यातों को आश्रित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपयोग्यता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में बढ़े हुए साहायिकी प्राप्त निर्यातों की संभाव्यता उपदर्शित होती हो,

(iv) क्या आयात ऐसी कीमतों पर किए जा रहे हैं जिनका प्रभाव देशी कीमतों को महत्वपूर्ण रूप में कम करना या दबाना होगा और जिससे और अधिक आयातों की मांग में वृद्धि होने की संभावना होगी; और

(v) अन्वेषण किए जा रहे उत्पादों की सूची।

उपाबंध—2

ऐसी साहायिकी के अवधारण के लिए सिद्धान्त को उत्पादन करने या निर्यात करने में लगे सीमित व्यक्तियों को प्रदान की गई है:

1. अभिहित प्राधिकारी इस बात की अवधारणा करने की दृष्टि से कि क्या कोई साहायिकी उत्पादन करने या निर्यात करने में लगे सीमित व्यक्तियों को प्रदान की गई है, निम्नलिखित सिद्धान्तों पर विचार करेगा:

(क) क्या अनुदत्त करने वाला प्राधिकारी या वह विधान, जिसके अनुसरण में अनुदत्त करने वाला प्राधिकारी कार्य करता है, साहायिकी को स्पष्ट रूप से कतिपय उद्यमों पर सीमित करता है। तथापि, जहां अनुदत्त करने वाला प्राधिकारी या विधान जिसके अनुसरण में अनुदत्त करने वाला प्राधिकारी कार्य करता है, किसी साहायिकी के लिए, पात्रता और उसकी रकम को आश्रित करने वाली वस्तुपरक कसौटियां या शर्तें स्थापित करता है तो साहायिकी उत्पादन करने या निर्यात करने में सीमित व्यक्तियों को दी हुई नहीं मानी जाएगी; परन्तु यह तब जब कि पात्रता स्वतः बनती हो और ऐसी कसौटियों या शर्तों का दृष्टापूर्वक अनुपालन किया जाता हो और ऐसी कसौटियां और शर्तें अनुदत्त करने वाले देश या राज्यक्षेत्र की विधि, विनियम या अन्य आसकीय दस्तावेज में स्पष्टतया परिभाषित की गई हो और उनका सत्यापन किया जा सकता हो।

स्पष्टीकरण:—उपरोक्त पैरा के प्रयोजन के लिए "वस्तुपरक कसौटियां या शर्तें" ये ऐसी कसौटियां या शर्तें अभिप्रेत हैं जो तटस्थ हैं, जो किन्हीं उद्यमों के साथ पक्षपात नहीं करती और जो भित्तवर्गी प्रकृति की हैं और लागू करने में, जैसे कर्मचारियों की संख्या या उद्योग के आकार, सम तत्सरीय हैं।

(ख) इस बात के अवधारण के होते हुए भी कि कोई साहायिकी ऊपर पैरा (क) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सीमित संख्या में उद्यमों को प्रदान की गई है, तो वह अन्य बातों पर विचार कर सकेगा, जैसे (1) कतिपय सीमित संस्था में उद्यमों द्वारा किसी साहायिकी कार्यक्रम का उपयोग या कतिपय उद्यमों द्वारा सर्वात्म्य उपयोग (2) कतिपय उद्यमों को अन्तर्जातक रूप में साहायिकी की बड़ी रकमें मंजूर करना और (3) वह रीति जिसमें अनुदत्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा साहायिकी के अवधारण के लिए, साहायिकी मंजूर करने का विनिश्चय करने में वियेकाधिकार का प्रयोग किया गया है। अभिहित प्राधिकारी यह खंड लागू करते समय अनुदत्त करने वाले प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के भीतर आर्थिक क्रियाकलापों के नानाम्बलपकरण की सीमा को और साथ ही उस समयव्यवधि को, जिसके दौरान साहायिकी कार्यक्रम प्रवर्तन में रहा, ध्यान में रखेगा।

(ग) ऐसी साहायिकी, जो अनुदत्त करने वाले प्राधिकारी का अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले अभिहित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर अवस्थित कतिपय उद्यमों तक सीमित रहे।

[क्र. सं. 525/2/94-सी.शु. (टीयू.)]

एल.एम. भटनागर, क्षेत्र अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 1995

No. 1/95-N.T. CUSTOMS

G.S.R. 2(LI).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 9 and sub-section (2) of Section 9-B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in super session of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Bounty-fed Articles and for Determination of Injury) Rules, 1983, except as respect things done or omitted to be done before such super-session, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the 1st day of January, 1995.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole of the like article, or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidized article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry;

Provided that in exceptional circumstances referred to in sub-rule (3) of rule 13, the domestic industry in relation to article in question shall be deemed to comprise two or more competitive

markets and the producers within each of such market be deemed as a separate industry if,—

(i) the producers within such market sell all or almost all of their production of the article in question in that market, and

(ii) the demand in the market is not in any substantial degree supplied by producers of the said article located elsewhere in the territory;

(c) "interested party" includes—

(i) an exporter or foreign producer or the importer of an article subject to investigation for being subsidized or a trade or business association a majority of the members of which are producers, exporters or importers of such an article; and

(ii) a producer of the like article in India or a trade and business association a majority of the members of which produce the like article in India;

(d) "provisional duty" means a countervailing duty imposed under sub-section (2) of section 9-A of the Act;

(e) "specified country" means a country or territory which is a member of the World Trade Organisation and includes the country or territory with which the Government of India has an agreement for giving it the most favoured nation treatment;

(f) all words and expressions used in these rules, but not defined, shall have to meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Appointment of designated authority.—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette appoint a person not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India or such other person as that Government may think fit as the designated authority for purposes of these rules.

(2) The Central Government may provide to the designated authority the services of such other persons and such other facilities as it deems fit.

4. Duties of the designated authority.—It shall be the duty of the designated authority in accordance with these rules—

(a) to investigate the existence, degree and effect of any subsidy in relation to the import of an article;

(b) to identify the article liable for countervailing duty;

(c) to submit its findings, provisional or otherwise to the Central Government as to—

(i) the nature and amount of subsidy in relation to an article under investigation.

(ii) the injury or threat of injury to an industry established in India or material retardation to the establishment of an industry in India consequent upon the import of such articles from the specified countries.

(d) to recommend the amount of countervailing duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry and the date of commencement of such duty; and

(e) to review the need for continuance of countervailing duty.

5. Decision as to country of origin.—In cases where articles are not imported directly from the country of origin but are imported from an intermediate country, the provisions of these rules shall be fully applicable and any such transaction shall, for the purpose of these rules be regarded as having taken place between the country of origin and the country of importation.

6. Initiation of investigation.—(1) Except as provided in sub-rule (4) the designated authority shall initiate an investigation to determine the existence, degree and effect of alleged subsidy only upon receipt of a written application, by or on behalf of the domestic industry.

(2) An application under sub-rule (1) shall be in the form as may be specified by the designated authority in this behalf and the application shall be supported by evidence of—

- (a) subsidy and, if possible, its amount
- (b) injury where applicable, and
- (c) where applicable, a casual link between such subsidized imports and alleged injury.

(3) The designated authority shall not initiate an investigation pursuant to an application made under sub-rule (1) unless—

- (a) it determines, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to the application expressed by domestic producers of the like article, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry;

Provided that no investigation shall be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less than twenty five per cent of the total production of the like product by the domestic industry, and

- (b) it examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies itself that there is sufficient evidence regarding—
 - (i) subsidy,
 - (ii) injury, where applicable; and
 - (iii) where applicable, a casual link between such subsidized imports and the alleged injury, to justify the initiation of an investigation.

Explanation.—For the purpose of this rule, the application shall be considered to have been made "by or on behalf of domestic industry" if it is supported by those domestic producers whose collective output constitutes more than fifty per cent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition as the case may be, to the application.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the designated authority may initiate an investigation suo-motu, if it is satisfied from the information received from the Collector of Customs appointed under the Customs Act, 1962 (51 of 1962) or any other source that sufficient evidence exists as to the existence of the circumstances referred to in sub-clause (b) of sub-rule (3).

(5) The designated authority shall notify the government of the exporting country before proceeding to initiate an investigation.

7. Principles governing investigations.—(1) The designated authority shall, after it has decided to initiate investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged subsidization of any article, issue a public notice notifying its decision. Police notice regarding initiation of investigation shall, inter-alia, contain adequate information on the following :

- (i) the name of the exporting countries and the article involved;
- (ii) the date of initiation of the investigation;
- (iii) a description of the subsidy practice or practices to be investigated;
- (iv) a summary of the factors on which the allegation of injury is based;
- (v) the address to which representations by interested countries and interested parties should be directed; and
- (vi) the time-limits allowed to interested countries and interested parties for making their views known.

(2) A copy of the public notice shall be forwarded by the designated authority to the known exporters of the article alleged to have been subsidized, the government of the exporting country concerned and other interested parties.

(3) The designated authority shall also provide a copy of the application referred to in sub-rule (1) of rule 6 to—

- (i) the known exporters or the concerned trade association where the number of exporters is large, and
- (ii) the government of the exporting country :

Provided that the designated authority shall also make available a copy of the application, upon request in writing, to any other interested party.

(4) The designated authority may issue a notice calling for any information in such form as may be specified by it from the exporters, foreign producers and governments of interested countries and such information shall be furnished by such persons in writing within thirty days from the date of receipt of the notice or within such extended period as the designated authority may allow on sufficient cause being shown.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule the public notice and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which these documents were sent by the designated authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country.

(5) The designated authority shall also provide opportunity to the industrial users of the article under investigation, and to representative consumer organisations in cases where the article is commonly sold at retail level, to furnish information which is relevant to the investigation regarding subsidization and where applicable injury and causality.

(6) The designated authority may allow an interested country or an interested party or its representative to present information relevant to the investigation orally also, but such oral information shall be taken into consideration only when it is subsequently reproduced in writing.

(7) The designated authority shall make available the evidence prescribed by one party to other interested parties participating in the investigation.

(8) In a case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the designated authority may record its findings on the basis of facts available to it and make such recommendations to the Central Government as it deems fit under such circumstances.

8. Confidential informations.—(1) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), (2), (3) and (7) of rule 7, sub-rule (2) of rule 11, sub-rule (4) of rule 17 and sub-rule (3) of rule 19 copies of applications received under sub-rule (1) of rule 6 or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof in sufficient details to permit a reasonable understanding of the substance of the confidential information and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority, is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information

is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

9. Accuracy of the information.—Except in cases referred to in sub-rule (8) of rule 7 the designated authority shall during the course of investigation satisfy itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties upon which its findings are based.

10. Investigation in the territory of other specified countries.—(1) The designated authority may carry out investigations in the territories of other countries, in order to verify the information provided or to obtain further details :

Provided that the designated authority notifies to such country in advance and such country does not object to such investigation.

2. The designated authority may also carry out investigations at the premises of any commercial organisation and may examine its records if such organisation agrees and if the country in whose territory the said commercial organisation is situated, is notified and has not raised any objection for the conduct of such investigation.

11. Nature of subsidy.—(1) The designated authority while determining the subsidy shall ascertain as to whether the subsidy under investigation—

- (a) relates to export performance, or
- (b) relates to the use of domestic goods over imported goods in the export article, or
- (c) it has been conferred on a limited number of persons engaged in manufacturing, producing or exporting the article unless such a subsidy is for—
 - (i) research activities conducted by or on behalf of persons engaged in the manufacture, production or export; or
 - (ii) assistance to disadvantaged regions within the territory of the exporting country; or
 - (iii) assistance to promote adaptation of existing facilities to new environmental requirements :

Provided that for the purposes of sub-clauses (a) and (b), subsidies of a kind mentioned in the Agreement on Agriculture, contained in the Final Act of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, shall not be taken into consideration.

Explanation.—(1) For the purposes of sub-clause (1) of clause (c) the term "subsidy for research activity" means assistance for research activities conducted by commercial organisations or by higher education or research establishments on a contract basis with the commercial organisations if the assistance covers not more than seventy five per cent of the costs of industrial research or fifty per cent of the costs of pre-competitive development activity and provided that such assistance is limited exclusively to—

- (i) costs of personnel (researchers, technicians and other supporting staff employed exclusively in the research activity);
- (ii) costs of instruments, equipment, land and buildings used exclusively and permanently (except when disposed of on a commercial basis) for the research activity;
- (iii) costs of consultancy and equivalent services used exclusively for the research activity, including brought in research, technical knowledge, patents, etc. ;
- (iv) additional overhead costs incurred directly as a result of the research activity; and
- (v) other running costs (such as those of materials, supplies and the like), incurred directly as a result of the research activity.

(2) For the purpose of sub-clause (ii) of clause (c), the term "subsidy for assistance to disadvantaged regions" means assistance to disadvantaged regions within the territory of the exporting country given pursuant to a general framework of regional development and such subsidy has not been conferred on limited number of enterprises within the eligible region :

Provided that—

- (a) each disadvantaged region must be a clearly designated contiguous geographical area with a definable economic and administrative identity;
- (b) the region is considered as disadvantaged on the basis of neutral and objective criteria, indicating that the region's difficulties arise out of more than temporary circumstances; such criteria must be clearly spelled out in law, regulation, or other official document, so as to be capable of verification;
- (c) the criteria shall include a measurement of economic development which shall be based on at least one of the following factors.—
 - (i) one of either income per capita or household income per capita, or Gross Domestic Product per capita, which must not be above eighty five per cent of the average for the territory concerned ;
 - (ii) unemployment rate, which must be at least one hundred and ten per cent of the average for the territory concerned, as measured over a three-year period; such measurement, however, may be a composite one and may include other factors.

(3) For the purposes of sub-clause (iii) of clause (c), "subsidy for assistance to promote adaptation of existing facilities to new environmental requirements" means assistance to promote adaptation of existing facilities to new environmental requirements imposed by law and/or regulations which result in greater constraints and financial burden on commercial organisations :

Provided that the assistance—

- (i) is a one-time non-recurring measure; and
- (ii) is limited to twenty per cent of the cost of adaptation; and
- (iii) does not cover the cost of replacing and operating the assisted investment, which must be fully borne by commercial organisations ; and
- (iv) is directly linked to and proportionate to a commercial organisation's planned reduction of nuisances and pollution, and does not cover any manufacturing cost savings which may be achieved; and
- (v) is available to all firms which can adopt the new equipment and/or production processes.

(3) The designated authority while determining the subsidy of a kind as referred to in sub-clause (c) to sub-rule (1) shall take into account, inter-alia the principles laid down in Annexure II to these rules.

12. Conferment of benefit.—The designated authority while determining the conferment of benefit to the recipient, pursuant to a subsidy, shall take into account the following guidelines—

- (a) government provision of equity capital shall not be considered as conferring a benefit, unless the investment decision can be regarded as inconsistent with the usual investment practices (including for the provision of risk capital of private investors in the territory of the granting country.
- (b) a loan by a government shall not be considered as conferring a benefit, unless there is a difference between the amount that the commercial organisation receiving the loan pays on the government loan and the amount it would pay on a comparable commercial loan which it could actually obtain on the

market. In this case the benefit shall be the difference between these two amounts:

- (c) a loan guarantee by a government shall not be considered as conferring a benefit, unless there is a difference between the amount that the commercial organisation receiving the guarantee pays on a loan guaranteed by the government and the amount that it would pay on a comparable commercial loan in the absence of the government guarantee. In this case the benefit shall be the difference between these two amounts adjusted for any differences in fees;
- (d) the provision of goods or services or purchase of goods by a government shall not be considered as conferring a benefit unless the provision is made for less than adequate remuneration, or the purchase is made for more than adequate remuneration. The adequacy of remuneration shall be determined in relation to prevailing market conditions for the goods or service in question in the country of provision or purchase (including price, quality, availability, marketability, transportation and other conditions of purchase or sale).

13. Determination of injury.—(1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall give a further finding that the import of such article into India causes or threatens material injury to any industry established in India, or materially retards the establishment of an industry in India.

(2) Except when a finding of injury is made under sub-rule (3), the designated authority shall determine the injury, threat of injury, material retardation to the establishment of an industry and the causal link between the subsidised import and the injury, taking into account inter-alia, the principle laid down in Annexure I to the rule.

(3) The designated authority may, in exceptional cases, give a finding as to the existence of injury even where a substantial portion of the domestic industry is not injured if—

- (i) there is a concentration of subsidised imports into an isolated market and;
- (ii) the subsidised imports are causing injury to the producers of almost all of the production within such market.

14. Preliminary findings.—(1) The designated authority shall proceed expeditiously with the conduct of the investigation and shall, in appropriate cases, record a preliminary finding regarding existence of a subsidy and its nature and in respect of imports from specified countries, it shall also record its preliminary finding regarding injury to the domestic industry and such finding shall contain sufficiently detailed explanation for the preliminary determination on the existence of a subsidy and injury and shall refer to the matter of fact and law which have led to arguments being accepted or rejected. Such finding shall contain—

- (i) the names of the suppliers or, when this is impracticable, the supplying countries involved;
- (ii) a description of the product which is sufficient for customs purposes;
- (iii) the amount of subsidy established and the basis on which the existence of a subsidy has been determined;
- (iv) consideration relevant to the injury determination; and
- (v) the main reasons leading to the determination.

(2) The designated authority shall issue a public notice recording its preliminary findings.

15. Levy of provisional duty.—The Central Government may, in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 9 of the Act, impose a provisional duty on the basis of the preliminary findings recorded by the designated authority.

Provided that no such duty shall be imposed before the expiry of sixty days from the date of issue of the public notice by the designated authority regarding its decision to initiate investigations;

Provided further that such duty shall remain in force for a period not exceeding four months.

16. Termination of investigation.—(1) The designated authority shall, by issue of a public notice terminate an investigation immediately if—

- (a) it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated;
- (b) it is satisfied in the course of an investigation, that there is no sufficient evidence either for subsidisation or, where applicable, injury to justify continuation of the investigation;
- (c) it determines that the amount of subsidy is less than one per cent advalorem or in the case of a product originating from a developing country the amount of subsidy is less than two per cent.
- (d) it determines that the volume of the subsidized imports, actual or potential or injury where applicable, is negligible or in the case of a product originating in a developing country the volume of the subsidized imports represents less than four per cent of the total imports of the like product into India, unless imports from developing countries whose individual shares of total imports represent less than four per cent collectively account for more than nine per cent of the total imports of the like product into India.

17. Suspension or termination of investigation on acceptance of price undertaking.—(1) The designated authority may suspend or terminate an investigation, if—

- (a) the government of the exporting country—
 - (i) furnishes an undertaking that it would withdraw the subsidy;
 - (ii) in case of specified countries, undertakes to limit the quantum of subsidy within reasonable limit, or to take other suitable measures to neutralise the effect of such subsidy, provided that the designated authority is satisfied that the injurious effect of the subsidy is eliminated, or
- (b) in case of specified countries the exporters concerned agree to revise their prices so that injurious effect of subsidy is eliminated and the designated authority is satisfied that the injurious effect of the subsidy is eliminated;

Provided that increase in price as a result of this clause is not higher than what is necessary to eliminate the amount of subsidy;

Provided further that the designated authority shall complete the investigation and record its finding, if the Central Government so desires or the government of the exporting country so decides.

(2) No undertaking as regards price increase under sub-rule (1) shall be accepted unless the designated authority had made preliminary determination of subsidization and the injury;

Provided that an undertaking from an exporter shall be accepted only when the designated authority has also obtained the consent of the exporting country.

(3) The designated authority may also not accept undertakings offered by any country or any exporter, if it considers the acceptance of such undertaking as impracticable or as unacceptable for any other reason.

(4) The designated authority shall intimate the acceptance of an undertaking and suspension or termination of investigation to the Central Government and also issue a public notice in this regard. The public notice shall contain inter-alia, the nonconfidential part of the undertaking.

(5) In cases where an undertaking has been accepted by the designated authority the Central Government may not impose a duty under sub-section (2) of section 9 of the Act for such a period the undertaking acceptable to the designated authority remains valid.

(6) Where the designated authority has accepted any undertaking under sub-rule (1), it may require the government of the exporting country, or the exporter from whom such undertaking has been accepted to provide from time to time information relevant to the fulfilment of the undertaking and to permit verification of relevant data :

Provided that in case of any violation of any undertaking, the designated authority will intimate the Central Government and complete the investigation expeditiously.

(7) The designated authority shall suo motu or on the basis of any request received from exporters or importers of the article in question or any other interested person review from time to time the need for the continuance of any undertaking given earlier

18. Disclosure of information.—The designated authority, shall, before giving its final findings, inform all interested parties and interested countries of the essential facts under consideration which form the basis of its decision and permit the interested parties to defend their interest.

19. Final findings.—(1) The designated authority shall within one year from the date of initiation of an investigation determine as to whether or not the article under investigation is being subsidized and submit to the Central Government its final finding, as to—

- (a) (i) the nature of subsidy being granted in respect of the article under investigation and the quantum of such subsidy ;
- (ii) whether imports of such articles into India in the case of imports from specified countries, cause or threaten material injury to an industry established in India or materially retards the establishment of any industry in India and a causal link between the subsidized imports and such injury ; and
- (iii) whether a retrospective levy is called for and if so, the reasons therefor and the date of commencement of such levy.
- (b) its recommendation as to the amount of duty which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry :

Provided that the Central Government may in circumstances of exceptional nature extend further the aforesaid period of one year by six months :

Provided further that in those cases where the designated authority has suspended the investigation on the acceptance of a price undertaking as provided in rule 17 and subsequently resumes the same on violation of the terms of the said undertaking, the period for which investigation was kept under suspension shall not be taken into account while calculating the said period of one year.

(2) The final finding if affirmative, shall contain all information on the matter of facts and law and reasons which have led to the conclusion and shall also contain information regarding—

- (i) the names of the suppliers, or, when this is impractical, the supplying countries involved ;
- (ii) a description of the product which is sufficient for customs purposes ;
- (iii) the amount of subsidy established and the basis on which the existence of a subsidy has been determined ;
- (iv) considerations relevant to the injury determination ; and
- (v) the main reasons leading to the determination.

(3) The designated authority shall issue a public notice regarding its final findings.

20. Levy of duty.—(1) The Central Government may, within three months of the date of publication of the final findings by the designated authority under rule 19, impose, by notification in the Official Gazette, upon importation into India

of the article covered under the final finding, a countervailing duty not exceeding the amount of subsidy as determined by the designated authority under rule 19.

Provided that in case of imports from specified countries the amount of duty shall not exceed the amount which has been found adequate to remove the injury to the domestic industry.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) where a domestic industry has been interpreted according to the proviso to clause (b) of rule 2, a countervailing duty shall be levied only after the exporters have been given opportunity to cease exporting at subsidized prices to the area concerned or otherwise give an undertaking pursuant to rule 17 and such undertaking has not been promptly given and in such cases duty cannot be levied only on the product of specified producers which supply the area in question.

(3) If the final finding of the designated authority is negative, that is contrary to the prima facie evidence on whose basis the investigation was initiated, the Central Government shall within forty five days of the publication of final findings by the designated authority under rule 19, withdraw the provisional duty, imposed if any.

21. Imposition of duty on non-discriminatory basis.—Any countervailing duty imposed under rule 15 or 20 shall be on a non-discriminatory basis and applicable to all imports of such article, if found to be subsidised and where applicable, causing injury except in the case of imports from those sources from which undertakings in terms of rule 17 have been accepted.

22. Date of commencement of duty.—(1) The countervailing duty levied under rule 15 and 20, shall take effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) —

(a) where a provisional duty has been levied and where the designated authority has recorded a finding of injury or here the designated authority recorded a finding of threat of injury and a further finding that the subsidised imports in the absence of provisional duty would have led to injury, the countervailing duty may be imposed from the date of imposition of provisional duty ;

(b) in the circumstances referred to in sub-section (1) of section 9 of the Act, the countervailing duty may be levied retrospectively from the date commencing ninety days prior to the imposition of provisional duty :

Provided that in case of violation of an undertaking referred to in sub-rule (6) of rule 17, no duty shall be levied retrospectively on imports which have entered for home consumption before violation of such terms of the undertaking.

23. Refund of duty.—(1) If the countervailing duty imposed by the Central Government on the basis of the final findings of the investigation conducted by the designated authority is higher than the provisional duty already imposed and collected the differential shall not be collected from the importer.

(2) If the countervailing duty fixed after the conclusions of the investigation is lower than the provisional duty already imposed and collected, the differential shall be refunded to the importer.

(3) If the provisional duty imposed by the Central Government is withdrawn in according with the provisions of sub-rule (3) of rule 20, the provisional duty already imposed and collected, if any shall be refunded to the importer.

countervailing duty and shall, if it is satisfied on the basis of information received by it that there is no justification for the continued imposition of such duty or additional duty, recommend to the Central Government for its withdrawal.

(2) Any review initiated under sub-rule (1) shall be concluded within a period not exceeding 12 months from the date of initiation of such review.

(3) The provisions of rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 and 23 shall mutatis mutandis apply in the case of review.

ANNEXURE I

PRINCIPLES GOVERNING THE DETERMINATION OF INJURY

The designated authority shall take into account inter-alia the following principles while determining injury:—

1. (1) A determination of injury for purposes of rule 13 shall be based on positive evidence and involve an objective examination of both (a) the volume of the subsidized imports and the effect of the subsidized imports on prices in the domestic market for like products and (b) the consequent impact of these imports on the domestic producers of such products.
- (2) With regard to the volume of the subsidized imports, the designated authority shall inter-alia consider whether there has been a significant increase in subsidized imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.
- (3) With regard to the effect of the subsidized import on prices, the designated authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the subsidized imports as compared with the price of a like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or to prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
- (4) Where imports of a product from more than one country are simultaneously subject to countervailing duty investigations, the designated authority may cumulatively assess the effect of such imports only if it determines that (a) the amount of subsidization established in relation to the imports from each country is more than one per cent ad valorem and the volume of imports from each country is not negligible and (b) a cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the like domestic product.
- (5) The designated authority while examining the impact of the subsidized imports on the domestic industry shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in output, sales, market share, profits, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment wages, growth, ability to raise capital investments and, in the case of agriculture, whether there has been an increased burden on government support programmes.
2. (1) It must be demonstrated that the subsidized imports are, through the effects of subsidies, causing injury. The demonstration of a causal relationship between the subsidized imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of all relevant evidence before the designated authority. The designated authority shall also examine any known factors other than the subsidized imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injuries caused by these other factors must not be attributed to the subsidized imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter-alia, the volumes and prices of non-subsidized imports of the product in question, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and productivity of the domestic industry.
- (2) The effect of the subsidized imports shall be assessed in relation to the domestic production of the like product when available data permit the separate identification of that production on the basis of such criteria as the production process, producers sales and profits. If such separate identification of that production is not possible, the effects of the subsidized imports shall be assessed by the examination of the production of the narrowest group or range of products, which includes the like product, for which the necessary information can be provided.

3. A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances which would create a situation in which the subsidy would cause injury must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the designated authority shall consider, inter-alia, such factors as:

- (i) nature of the subsidy or subsidies in question and the trade effects likely to arise therefrom;
- (ii) a significant rate of increase of subsidized imports into the domestic market indicating the likelihood of substantially increased importation;
- (iii) sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased subsidized exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
- (iv) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
- (v) inventories of the product being investigated.

ANNEXURE II

PRINCIPLES FOR DETERMINATION OF SUBSIDY WHICH HAS BEEN CONFERRED ON A LIMITED NUMBER OF PERSONS AS REFERRED TO IN RULE 11

1. The designated authority in order to determine as to whether a subsidy has been conferred on a limited number of persons engaged in the manufacture or production of an article, shall take the following principles into consideration:—

- (a) whether the granting authority or the legislation pursuant to which the granting authority operates, explicitly limits access to a subsidy to certain enterprises. However, where the granting authority, or the legislation pursuant to which the granting authority operates, establishes objective criteria or conditions governing the eligibility for, and the amount of, a subsidy, such subsidy shall not be considered to have been conferred on a limited number of persons engaged in the manufacture or production of an article, provided that the eligibility is automatic and such criteria or conditions are strictly adhered to and such criteria and conditions have been clearly spelt out in the law, regulation or other official document of the granting country or territory and are capable of verification.

Explanation.—For the purposes of the above para objective criteria or conditions mean criteria or condition which are neutral, which do not favour certain enterprises over others, and which are economic in nature and horizontal in application, such as number of employees or size of enterprises.

- (b) Notwithstanding the determination that a subsidy is not being granted to a limited number of enterprises in terms of the provisions contained in para (a) above, if the designated authority has reason to believe that the subsidy has in fact been conferred to a limited number of enterprises, it may consider other factors like (1) use of a subsidy programme by a limited number of certain enterprises of predominant use by certain enterprises, (2) granting of disproportionately large amounts of subsidy to certain enterprises, and (3) manner in which discretion has been exercised by the granting authority in decision to grant a subsidy, for determination of subsidy. The designated authority, in applying this clause, shall take into account, the extent of diversification of economic activities within the jurisdiction of the granting authority, as well as the length of the time during which the subsidy programme has been in operation.
- (c) A subsidy which is limited to certain persons engaged in the manufacture or production of an article located within a designated geographical region within the jurisdiction of the granting authority shall be considered to have been granted to a limited number of persons engaged in the manufacture or production.

[F. No. 525/2/94-C.U.(T)]
S. M. BHATNAGAR, Under Secy.